THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRIMATI ABHA MAITI): Yes, Sir. The Central Government has agreed to the proposal of the West Bengal Government to take over distribution through the State Agencies with effect from 1st October, 1978. A copy of the Scheme of the West Bengal Government is attached. The State Governments have been requested to give due consideration to this scheme to see whether a similar system or any other suitable mechanism for control distribution needs to be introduced in every State. In the meanwhile, in a meeting of the representatives of Cement Manufacturers' Association and Central and State Governments, it has been agreed that the voluntary distribution scheme introduced by the Cement Manufacturers' Association might be tried. This voluntary distribution scheme came into effect during July 1978.

Statement

Scheme for public distribution of cement in the State of West Bengal.

The Government of West Bengal has decided to take over the distribution of cement in West Bengal from 1st October, 1978. Bulk quantities of State allocation for the quarter (per taining to State Sector) will be placed at the disposal of the State Government. The State Government has appointed the West Bengal Essential Commodity Supply Corporation for distribution of cement within the State. This Corporation will further allocate the quantities to RC (State Government Departments, Public Sector undertakings, etc.)/ ORC parties (Small Scale Industries, Institutions, etc.) and free sale (for sale to public). The Regional Cement Controller will issue release orders in favour of RC and ORC parties on receipt of recommendations from this Corporation.

For sale of Cement to the public the Corporation has started scrutinising antecedents of existing stockists of cement factories. On approval, the selected stockists will be appointed by the Corporatioin as its own stockists. The Corporation will distribute the free sale allocation of its State amongst these stockists or such other public agencies as it may select for sale of cement in West Bengal. The stockists will deposit money with this Corporation and the Corporation will arrange supplies from the various cement factories which are linked with the State by Cement Controller for supply of cement during that particular quarter. The stockists will be directly answerable to the Corporation for sale of cement to public at the fixed retail price. The Corporation will retain full powers and control over the stockists and in case of malpractices indulged by any of its stockists it shall take prompt action to cancel the stockistship.

कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कमी

1529. श्री ग्रमन्तराम जायसवाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कपड़े के प्रति व्यक्ति खपत 1973 में 14.99 मीटर से घटकर वर्ष 1974 तथा 1975 में क्रमश: 13.63 मीटर तथा 13.31 मीटर हो गई थी ;

(ख) वर्ष 1976 तथा 1977 में ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में कपड़े की प्रति-व्यक्ति खपत कितनी रही ;

(ग) क्या कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कमी कपड़े के मूल्य बढ़ जाने से हुई है या इसका उत्पादन घट जाने से हुई है ; और

(घ) देश के गरीब लोगों की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माहति) : (क) वर्ष 1973 से 1976 तक प्रति व्यक्ति खपत के लिए कपड़े की उपलब्धता निम्न प्रकार है :—

	मीटर
1973 . .	13.94
1974 . .	14.60
1975 . .	14.56
1976 . .	13.73 (अनन्तिम)

(ख) ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति कपड़ें की खपत के प्रामाणिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). यह सच है कि कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कमी होती रही है। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से मन्दी की स्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है। टिकाऊ गैर-सूती धागे का अधिक प्रयोग करने के कारण कपड़े में आए अधिक टिकाऊपन से एवं विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में हुए परिवर्तनों के कारण भी प्रति व्यक्ति खपत में कमी हुई है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाकर कपड़े की प्रति व्यक्ति पूर्ति तथा खपत को कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। वस्त्रों की पूर्ति को बढ़ाने के प्रयासों को छठी योजना के कार्यक्रम के अंग के रूप में लिया जाए गा।

कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी

1530. **श्री अनन्तराम जायसवाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965–66 से कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में निरंतर कमी हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों में अलग-अलग प्रति व्यक्ति उपलब्धता और खपत के आंकड़े क्या हैं; और

(ग) प्रति व्यक्ति उपलब्धता के निरंतर कम होने के क्या कारण हैं और क्या इस उपलब्धता और खपत को बढ़ाने के लिये सरकार कोई उपाय कर रही है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माहति): (क) से (ग). क्या यह सच है कि कपड़े की प्रति व्यक्ति खपत में कमी होती रही है। यह प्रवृत्ति मुख्य रूप से मन्दी की स्थितियों के कारण उत्पन्न हुई है एवं विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में हुए परिवर्तनों के कारण उनकी मांग बढ़ने में रुक गई है। टिकाउ गैर-सूती धागे का अधिक प्रयोग करने के कारण कपड़े में आए अधिक टिकाऊपन के कारण भी प्रति व्यक्ति खपत में कमी हुई है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति को बढ़ाकर कपड़े की प्रति व्यक्ति पूर्ति तथा खपत को कुछ सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। वस्त्रों की पूर्ति को बढ़ाने के प्रयासों को छठी योजना के कार्यक्रम के अंग के रूप में लिया जायेगा। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े की उपलब्धता तथा उसकी खपत के बारे में अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं तथापि, वर्ष 1974 से 1976 की अवधि में, जिसके आंकड़े उपलब्ध हैं, खपत के लिए कपड़े की प्रति व्यक्ति उपलब्धता निम्न प्रकार है :—

1974	14.60 मीटर
1975	14.56 मीटर
1976	13.73 मीटर (अनन्तिम)